देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित | www.page3news.in | नगर संस्करण वर्ष 15 अंक: 145 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...शिंजो आबे के इस्तीफा

पेज थ्री

देहरादून, मंगलवार, 8 सितंबर 2020

मौसम अधिकतम 30.0° न्यूनतम 22.0° | 38040.57 | 2 भारत के ऐक्शन से घबराया चीन | 7 नोवाक जोकोविच हुए डिस्क्वॉलिफाई

संक्षिप्त समाचार

स्वास्थ्य महानिदेशालय में कोरोना की दस्तक आ धमकी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

देहरादून। राज्य के स्वास्थ्य महानिदेशालय में कोरोना की दस्तक आ धमकी है। स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर कर्मचारियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है जिसके बाद महानिदेशालय में हड़कंप मचा हुआ है। उल्लेखनीय है कि पहले ही डेढ़ दर्जन से ज्यादा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और उस दौरान कार्यालय को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया और जबकि आज तीन और कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य महानिदेशालय में तैनात कर्मचारी लगातार कोरोना पॉजिटिव आ रहे है।

रिया ने सुशांत की बहन के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

मुबंई। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी गर्लफ्रेंड रहीं रिया चक्रवर्ती की टीम ने सुशांत की बहन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। रिया की यह शिकायत सुशांत सिंह राजपूत को फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दिए जाने के मामले में की गई है। रिया चक्रवर्ती से इस समय एनसीबी ड्रग चौट केस में पूछताछ कर रहा है और माना जा रहा है कि इस मामले में रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। रिया चक्रवर्ती ने अपनी शिकायत ने पहली बार सुशांत की बहन प्रियंका पर उन्हें ड्रग्स देने का आरोप लगाया है।

नीरव मोदी को भारत को प्रत्यर्पित करने पर सुनवाई शुरू

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

लंदन। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को लेकर दायर मुकदमे की सुनवाई लंदन की अदालत में शुरू हो गई है। वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट की अदालत में इस मामले की सुनवाई अगले पांच दिनों तक चलेगी। माना जा रहा है कि इस दौरान यह साफ हो जाएगा कि नीरव मोदी को भारत कब प्रत्यर्पित किया जाएगा। वहीं, नीरव मोदी के वकील ने अदालत से प्रेस को इस कार्यवाही की कवरेज से दूर रखने का आग्रह किया है।

सरकार की नहीं देश की है शिक्षा नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

- सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने लिया भाग

नई दिल्ली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक शिक्षा और स्किल्स दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी। वहीं, राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों में शिक्षकों की केन्द्रीय भूमिका रहेगी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का विषय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बदलावों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की भूमिका रखा गया है। इसमें सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालयों के कुलपति भाग ले रहे हैं।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये शिक्षा नीति, सरकार की शिक्षा नीति नहीं है। ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति देश की नीति होती है, रक्षा नीति देश की नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी देश की ही नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भविष्य को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रावधान किए गए है। जैसे–जैसे तकनीक का विस्तार गांवों तक हो रहा है। वैसे–वैसे सूचना और शिक्षा का एक्सेस भी बढ़ रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर कॉलेज में तकनीकी सॉल्यूशंस को ज्यादा प्रमोट करें।

21वीं सदी के भारत को नई दिशा मिलेगी: उन्होंने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ पढ़ाई के तौर तरीकों में बदलाव के लिए ही नहीं है। ये 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक पक्ष को नई दिशा देने वाली है। ये आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और सामर्थ्य को आकार देने वाली है। गांव में कोई शिक्षक हो या फिर बड़े–बड़े शिक्षाविद, सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अपनी शिक्षा शिक्षा नीति लग रही है। सभी के मन में एक भावना है कि पहले की शिक्षा नीति में यही सुधार मैं होते हुए देखना चाहता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्वीकारता की बड़ी वजह यही हैरू पीएम मोदी

देश भर में सम्मेलनों का आयोजन गौरतलब है कि देशभर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं पर कई वेबिनार, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछले दिनों राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन आयोजित किया था।

कम होना चाहिए सरकार का दखल

पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, सभी जुड़े होते हैं। लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव, कम से कम होना चाहिए। शिक्षा नीति से जितना शिक्षक, अभिभावक जुड़े होंगे, छात्र जुड़े होंगे, उतना ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता, दोनों ही बढ़ती है।

शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों के सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 21वीं सदी की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को आगे ले जाने में सक्षम होगी। यह केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के शिक्षार्थियों एवं नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों में शिक्षकों की केन्द्रीय भूमिका रहेगी।

चीन ने अरूणाचल प्रदेश को बताया अपना हिस्सा

भारतीय बंधकों पर कुछ नहीं दिया जवाब

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

- चीन की पीपल्स लिब्रेशन आर्मी ने अगवा किया

पेइचिंग। भारत के अरुणाचल प्रदेश से 5 भारतीय युवकों का अपहरण करने वाला चीन अब दादागिरी पर उतारू हो गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन से जब इन युवकों के बारे में पूछा गया तो उसने भारतीयों के बारे में जानकारी देने की बजाय अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बता दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के अनुरोध के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

लिजिन ने कहा, चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है जो चीन का दक्षिणी तिब्बत इलाका है। भारतीय सेना के पीएलए को भारतीयों को छोड़ने के लिए संदेश भेजने के सवाल पर चीनी प्रवक्ता ने कहा कि हमारे पास अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के 5 युवकों इन युवकों को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने उनको अगवा किया है। गांववालों का दावा है कि ये युवक भारतीय सेना के लिए पोर्टर के रूप में काम करते थे जो दुर्गम क्षेत्रों में सामान की ढुलाई करते थे। यह भी कहा जा रहा है कि ये युवक संभवतरू जंगल की ओर गए होंगे जहां से ये चीनी सेना के हत्थे चढ़े। लापता आदिवासी युवकों में से एक के भाई ने फेसबुक पर पोस्ट किया था कि चीनी सेना नाचो के पास इंटरनैशनल बॉर्डर (आईबी) से भारतीय सेना के सेरा–7 पेट्रोलिंग इलाके से भारतीय युवकों को उठा ले गई है।

की अपहरण की जांच के लिए एक पुलिस टीम को मैकमोहन लाइन से सटे सीमावर्ती क्षेत्र में भेजा गया है। यह लाइन अपर सुबनसिरी जिले को तिब्बत से अलग करती है। यह जगह जिला मुख्यालय दापोर्जियो से 120 किमी दूर उत्तर की ओर है। फेसबुक पोस्ट के बाद ही जिला प्रशासन अलर्ट हुआ। नाचो गांव सेरा–7 से करीब 10 से 12 किमी दूर स्थित है, यहां के लोगों का दावा है कि लापता युवक पोर्टर के रूप में सेना से जुड़े हुए थे जो सामान की ढुलाई करते हैं और इलाके में सड़क व मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से वे गाइड के रूप में काम करते हैं।

ऐसे चढ़े चीनी सेना के हत्थे? पूर्व मंत्री निनॉन्ग एरिंग ने कहा, यहां के लोगों का सेना के लिए पोर्टर के रूप में काम करना आम बात है। उन्होंने आशंका जताई, लापता युवक आर्मी पोस्ट में सामान की ढुलाई करने के बाद जरूर जंगलों में शिकार करने या जड़ी–बूटी इकट्ठा करने गए होंगे।

कंगना रनोट को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनोट को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। दरअसल, कंगना रनोट और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई थी। संजय राउत ने कंगना को मुंबई न आने की नसीहत दी थी. इस पर कंगना ने मुंबई आने का चैलेंज किया था।

अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना रनोट को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। उनकी सुरक्षा में 11 जवान तैनात रहेंगे। इसमें एक या दो कमांडो और बाकी पुलिसकर्मी होंगे। बताया जा रहा है कि 9 सितंबर को जब कंगना मुंबई पहुंचेंगी, उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल जाएगी।

बता दें कि कंगना ट्विटर पर आने के बाद से ही एक बार फिर से चर्चा में हैं। मुंबई पुलिस को लेकर बयान के बाद से कंगना को लेकर शिवसेना हमलावर हो गई है। शिवसेना ने कंगना को लेकर अपने तेवर काफी तीखे कर लिए हैं और इन हालात को देखते हुए कंगना के पिता ने हिमाचल प्रदेश सरकार से पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। अब खबर है कि गृह मंत्रालय की ओर से अब कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है।

जुबानी जंग

अमित शाह ने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखाः कंगना रनोट

कंगना ने ट्वीट कर खुशी जताई कंगना ने खुद को मिली इस सुरक्षा को लेकर खुशी जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए लिखा, श्ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फासीवादी नहीं कुचल सकेगा,में अमित शाह जी की आभारी हूं। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी, जय हिंद।

Are you Planning to make a Website or already have ?
If yes, then we are here to serve you
What we do
Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.
Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS
Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.
Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

दुश्मन की हर चाल होगी नाकाम

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

- राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा निधि बनाना चाहता है गृह मंत्रालय

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने 15वें वित्व्त आयोग से 50 हजार करोड़ रुपये की शुरुआती रकम से राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा निधि बनाने को कहा है। इसका ज्यादा हिस्सा रियल टाइम सर्विलांस और इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्नोलॉजी ऐंड गैजेट्स पर खर्च होने की उम्मीद है। एनके सिंह की अध्यक्षता वाली एफएफसी को लिखी चिट्ठी में मंत्रालय ने कहा है कि आंतरिक सुरक्षा केंद्र और राज्यों की साझा जिम्मेदारी है। इसलिए ऐसा फंड बनाना सही है। 26 अगस्त को ईमेल से भेजे गए सवालों का गृह मंत्रालय और एफएफसी ने जवाब नहीं दिया।

राष्ट्रीय सुरक्षा निधि के बाद अलग से बनेगी आंतरिक सुरक्षा निधिः सरकार ने पिछले साल नवंबर में 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 11 महीने बढ़ा दिया था। रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आयोग रास्ते खोज सके, उसका भी इंतजाम था। रक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय सुरक्षा निधि बनाने की बात की थी। अब गृह मंत्रालय चाहता है कि NISF अलग से बने और वही उसे मैनेज करे।